भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3122
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

मोबाइल और दूरसंचार नेटवर्क रहित क्षेत्र

3122. डॉ. आनन्द कुमार गोंड

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश के कई क्षेत्रों में मोबाइल और दूरसंचार नेटवर्क रहित क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट्स) मौजूद हैं, जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी हैं, जिसके कारण नागरिकों को कॉल ड्रॉप, इंटरनेट व्यवधान और आपातकालीन संचार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिह्नित किए गए मोबाइल/दूरसंचार 'ब्लैक स्पॉट्स' की संख्या कितनी है और इसका राज्य/शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मोबाइल टावरों की स्थापना, नेटवर्क घनत्व बढ़ाने, 4जी/5जी विस्तार या वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उक्त 'ब्लैक स्पॉट' क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है; और

(घ) उक्त उपायों की वर्तमान प्रगति क्या है और निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) वर्तमान में, दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों ने बताया है कि देश के लगभग 8,985 गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध नहीं (ब्लैकस्पॉट्स) हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता नियमित ड्राइव टेस्ट द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा से वंचित क्षेत्रों की पहचान करते हैं और मौजूदा नेटवर्क को इष्टतम बनाकर और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार नए बेस ट्रांसीवर

स्टेशन (बीटीएस) स्थापित करके कवरेज प्रदान करते हैं। सेवा से वंचित गांवों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ग) और **(घ)** देश के सेवा से वंचित दूरस्थ और ग्रामीण गांवों और द्वीपसमूहों को उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट / ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

i. **भारत नेट परियोजना:** देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। जनवरी-2026 तक, भारतनेट परियोजना के तहत देश में 2,14,921 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 04.08.2023 को सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) को भारत नेट चरण-1 और चरण-2 के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों (जीपी) में नेटवर्क का निर्माण करने और मांग के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायतों (जीपी) से शेष ग्राम पंचायत विहीन गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

ii. **4जी सेचुरेशन:** देश में जनवरी-2026 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित 4जी सेचुरेशन परियोजना और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के तहत 23,994 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

iii. **सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल:** चेन्नई एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बीच (2312 किमी) और मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच (1869 किमी) सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की कमीशनिंग। एफटीटीएच और अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 225 किमी ओएफसी नेटवर्क का निर्माण। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं से द्वीपसमूह में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड / इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) और अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं को तेजी से रोल आउट करने की सुविधा मिली है।

अनुबंध-I

दिनांक 31.01.2026 तक सेवा से वंचित गांवों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची		
क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**सेवा से वंचित गांवों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	127
2	आंध्र प्रदेश	394
3	अरुणाचल प्रदेश	1,185
4	असम	163
5	बिहार	39
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	769
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0
9	गोवा	38
10	गुजरात	213
11	हरियाणा	1
12	हिमाचल प्रदेश	510
13	जम्मू और कश्मीर	248
14	झारखंड	324
15	कर्नाटक	470
16	केरल	0
17	लद्दाख	10
18	लक्षद्वीप	0
19	मध्य प्रदेश	960
20	महाराष्ट्र	872
21	मणिपुर	191
22	मेघालय	159
23	मिजोरम	54
24	नागालैंड	131
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0
26	ओडिशा	1,237
27	पुडुचेरी	0
28	पंजाब	2
29	राजस्थान	531
30	सिक्किम	6
31	तमिलनाडु	3
32	तेलंगाना	228
33	त्रिपुरा	7
34	उत्तर प्रदेश	36
35	उत्तराखंड	68
36	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	**8,985**

*****